जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 13 संख्याः 318 प्रभात चूरू, गुरुवार 17 मार्च, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

गहलोत के प्रयास पूर्णतया विफल हुए

जी-23 नेताओं ने गुलाम नबी के निवास पर बैठक कर, कई प्रस्ताव फाइनल किये, सोनिया गांधी के समक्ष बातचीत के लिये

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। अशोक गहलोत की मध्यस्थता की कोशिशें तथा गांधी परिवार की आलोचना को रोकने की कोशिशें पूरी तरह विफल हो गईं क्योंकि जी-23, जो वरिष्ठ नेताओं का एक अनौपचारिक ग्रुप हैं, की आज शाम मीटिंग हुई, ताकि गांधी परिवार पर दबाव डाला जा सके कि वह अब जाग जाये तथा उन चुनावी नुकसानों का उपचार करे, जिन्होंने पार्टी को हिला कर रख दिया हैं।

- जी-23 नेताओं ने एक प्रस्ताव भी पारित किया तथा एक सामूहिक व इन्क्लूसिव बातचीत का तरीका अपनाने की बात कही, कोई निर्णय लेने से पहले।
- प्रस्ताव में नेतृत्व परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं है।
- पर यह भी सच है कि कपिल सिब्बल ने जरूर यह कहा कि, गांधी परिवार को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिये, जिससे नया नेतृत्व उभर कर आये।
- जी-23 की बैठक में शशि थरूर, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवाड़ी, पृथ्वीराज चौहान, भूपेन्द्र सिंह हूडा, परनीत कौर, मणिशंकर अय्यर, वघेला व संदीप दीक्षित भी उपस्थित थे।
- यह संख्या, लगता है और बढ़ेगी, पर गांधी परिवार के युवा, जी-23 के इन सुझावों को सुनने को तैयार हैं क्या।

मीटिंग में एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वे लोग हाल ही के चुनावों के परिणामों से चिन्तित हैं तथा चाहते हैं कि निर्णय लेने के मामले में सामूहिक तथा समावेशी संवाद होना चाहिये। बयान में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और न गांधी-परिवार पर कोई हमला ही किया गया है। लेकिन यह पहला अवसर है, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो जी-23 में भी शामिल हैं, ने सार्वजनिक रूप से कहा कि गांधी परिवार इस्तीफा दे और किसी अन्य नेता के लिये रास्ता साफ करे।

कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है तथा समय आ गया है कि नेतृत्व किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी-नेतृत्व सौंप दे।

इस बयान ने पार्टी में मानो खलबली मचा दी है। जबकि गांधी परिवार को ऐसा लग रहा था कि वह इस ताजातरीन संकट पर बिना किसी खास नुकसान के पार पा लेगा।

ऐसी संभावना है कि गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी तथा शायद गांधी भाई-बहिन से मिलें तथा उन प्रस्तावों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

राष्ट्रपति के चुनाव पर भी दो-दो हाथ करेंगी ममता

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। राज्य विधानसभा चुनावों, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनैतिक हस्ती के रूप में उभरने की ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल गई है, में मिली घोर पराजय के बाद, अब वे भाजपा को एक नई चुनौती दे रही हैं।

ममता ने कहा है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर टक्कर होगी, जो इस वर्ष के अन्त में ही होने चाहिये।

- ममता का सोच है, राष्ट्रपति का चुनाव आसान नहीं होगा भाजपा के लिये, क्योंकि देश में आधे विधायक नहीं हैं भाजपा के साथ।

ममता ने आज मीडिया से बात करते हुये इस संबंध में अपने विचार बताये तथा कहा कि भाजपा युद्ध के इस राउन्ड को जीतने की स्थिति में नहीं है।

भारत के राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसके अन्तर्गत, संसद सदस्यों, मतदाता मंडल (इलैक्टोरल कॉलेज) इस सर्वोच्च पद के लिये अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है। इसके बाद, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अवकाश की सूचना

होली पर्व के अवसर पर दैनिक राष्ट्रदूत कार्यालय में दिनांक 17 व 18 मार्च को अवकाश रहेगा। अतः दैनिक राष्ट्रदूत का अगला अंक 20 मार्च को प्रकाशित होगा।

-प्रबंध सम्पादक

राजस्थान में फिर जगी नए जिलों के गठन की आशा

मुख्यमंत्री ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी, छः महीने में देगी रिपोर्ट

जयपुर, 16 मार्च (का.प्र.)। प्रदेश के कई क्षेत्रों से लंबे समय से अलग-अलग जिलों के गठन की मांग उठती रही है। नीम का थाना, कोटपूतली, शाहपुरा, बालोतरा, डीडवाना, फलोदी, ब्यावर सहित करीब एक दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें जिला बनाने की मांग की जाती रही है और उसको लेकर आंदोलन होते रहे हैं।

संभावना जताई जा रही थी कि इस बार के बजट में राजस्थान में नए जिलों के गठन की घोषणा होगी लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक भी नया जिला बनाने की घोषणा नहीं की। ऐसे में विधायकों की नाराजगी भी सामने आई और पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने तो पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार बालोतरा को जिला नहीं बनाए जाने तक जूते नहीं पहनने की कसम खा ली।

अब बजट सत्र चल रहा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान में नए जिलों के गठन की आशा जगाई है। नए जिलों के गठन के उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की। यह कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंपेंगी।

गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता का आंकलन करने के संबंध में जिस उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है, उसके अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया होंगे। प्रमुख शासन सचिव (राजस्व विभाग) समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख शासन सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज), प्रमुख शासन सचिव (वित्त) और उनके प्रतिनिधि, जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे के न हों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की ओर से मनोनीत प्रतिनिधि, जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं।

यह समिति विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित आमजन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापनों और मांग पत्रों पर विचार कर नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन कर 6 माह में रिपोर्ट देगी।

हिजाब

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई से बुधवार को इंकार कर दिया जिसमें राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक का समर्थन किया गया था।

- सुप्रीम कोर्ट ने अविलम्ब, तुरन्त सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की।

वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने इस प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश एन.वी.

(शेष पृष्ठ 5 पर)